सदस्य बनें
सच और सरोकार की पत्रकारिता से जुड़ें
वार्षिक सदस्यता : ₹ 500 मात्र
पूरा वर्ष अखबार निःशुल्क
पैनल विज्ञापन दें
अपने व्यवसाय/संस्था का प्रचार करें 'जन जन विचार' में।
किफायती • प्रभावी • विश्वसनीय
संपर्क : 69001 26012

जन जन की बात जन जन तक
साप्ताहिक
जन जन विचार

D.S. Associates
Sri Om Plaza
2nd Floor, K.C. Road,
Chatribari, Guwahati-1
Phone : 7002682705

RNI Regd No. ASMUL/25/A2367::Guwahati, Friday, 24 April 2026 :: Vol-15 Year-1 :: शुक्रवार । 24 अप्रैल 2026 । शक संवत 1948 । वैशाख । शुक्ल । अष्टमी । :: पृष्ठ-8 । मूल्य – 5 रुपए

जन चिंतन
धनेश्वर चौधरी

अंकवादी मानसिकता

हाल ही में सीबीएसई के परीक्षा परिणाम घोषित हुए। हर वर्ष की तरह इस बार भी 'टॉपर्स' की लंबी सूची, 95-99 प्रतिशत अंक पाने वाले विद्यार्थियों की भरमार और 'रिकॉर्ड रिजल्ट' के दावे सुर्खियों में रहे। लेकिन इस चमक-दमक के पीछे एक गंभीर सवाल खड़ा है-क्या सच में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ रही है, या हम केवल अंकों की दौड़ में बच्चों का भविष्य खो रहे हैं?

आज स्थिति यह है कि 90 प्रतिशत अंक भी 'सामान्य' माने जाने लगे हैं। स्कूल, अभिभावक और स्वयं विद्यार्थी- सभी का ध्यान सिर्फ नंबर लाने पर केंद्रित हो गया है। पढ़ाई का उद्देश्य ज्ञान अर्जन नहीं, बल्कि मार्कशीट में अधिक अंक जोड़ना बन गया है। नतीजा यह है कि रटने की प्रवृत्ति बढ़ रही है, जबकि समझने और सोचने की क्षमता कमजोर पड़ती जा रही है।

सबसे चिंताजनक पहलू यह है कि इस होड़ में शेष पृष्ठ 2 पर

कृत्रिम बाढ़, असली मौतें

तीन शव बरामद :

लगातार बारिश और जलजमाव के बीच गुवाहाटी में 21 अप्रैल को अलग-अलग स्थानों से तीन शव बरामद किए गए, जिससे महानगर में दहशत का माहौल है। प्रशासन ने अभी तक मौतों को आधिकारिक तौर पर बाढ़ से नहीं जोड़ा है, लेकिन शुरुआती जांच में इन्हें संभावित रूप से जलजमाव से शेष पृष्ठ 7 पर

जन जन विचार
...✍ गुवाहाटी

हर चुनाव में 'स्मार्ट सिटी' और 'फ्लड-फ्री गुवाहाटी' के वादे महानगर की दीवारों से लेकर मंचों तक गूंजते हैं, लेकिन पहली तेज बारिश ही इन दावों की सच्चाई उजागर कर देती है। गुवाहाटी आज उस मोड़ पर खड़ा है जहां बाढ़ सिर्फ प्राकृतिक आपदा नहीं रह गई, बल्कि यह एक ऐसी 'कृत्रिम त्रासदी' बन चुकी है जिसे हमने खुद अपनी योजनाओं, लापरवाहियों और अनियोजित विकास से जन्म दिया है।

कभी इस शहर के पास एक स्वाभाविक बढ़त थी- बिल, निचले इलाके, जल निकासी शेष पृष्ठ 3 पर

नाले जाम, सिस्टम फेल

गुवाहाटी। असम के मुख्य सचिव रवि कोटा ने चेतावनी दी है कि इस साल गुवाहाटी में जलजमाव की स्थिति पिछले वर्षों की तुलना में अधिक गंभीर है, जिसका एक बड़ा कारण ड्रेनों में जमा प्लास्टिक कचरा है। उन्होंने कहा कि इस बार अधिक वर्षा के चलते शेष पृष्ठ 7 पर

मणिपुर : खून, खौफ और बेघर जिंदगी

जन जन विचार
...✍ इंफाल

58 हजार से ज्यादा विस्थापित, 217 मौतें

पूर्वोत्तर के संवेदनशील राज्य मणिपुर में मई 2023 से जारी जातीय हिंसा अब एक लंबे मानवीय संकट का रूप ले चुकी है। राज्य के गृह विभाग द्वारा आरटीआई के जवाब में सामने आए आंकड़ों के मुताबिक, अब तक 58,821 लोग विस्थापित हो चुके हैं, जबकि 217 लोगों की मौत हो चुकी है। बड़ी संख्या में लोग घायल भी हुए हैं और हजारों परिवार आज भी राहत शिविरों में जीवन बिताने को मजबूर हैं।

सरकार के अनुसार, 10 मार्च 2026 तक राज्य में 174 राहत शिविर संचालित हो रहे हैं। विस्थापितों के पुनर्वास के लिए 3,000 प्री-फैब्रिकेटेड घर बनाए गए हैं, लेकिन हालात अब भी सामान्य नहीं हैं। यह आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं कि हिंसा ने सामाजिक और आर्थिक ढांचे को गहरी चोट पहुंचाई है।

इस बीच, भाजपा विधायक वुंगजागिन शेष पृष्ठ 5 पर

महंगी किताबें : निजी स्कूलों की मनमानी पर एनएचआरसी सख्त

जन जन विचार
...✍ नई दिल्ली

देशभर में निजी स्कूलों द्वारा महंगी किताबें थोपे जाने के आरोपों पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने कड़ा रुख अपनाते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय, सीबीएसई और सभी राज्यों-केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को नोटिस जारी किया है।

आयोग ने स्पष्ट कहा है कि यदि आरोप सही पाए गए तो यह शिक्षा के अधिकार कानून के प्रावधानों का उल्लंघन होगा और अभिभावकों पर 'अनुचित आर्थिक बोझ' डालने जैसा है।

शिकायत में शेष पृष्ठ 5 पर

बाजार में नहीं मिलतीं एससीईआरटी की किताबें

जन जन विचार
...✍ गुवाहाटी

असम में सस्ती और समान शिक्षा के दावों के बीच एक बड़ा विरोधाभास सामने आया है। एससीईआरटी की पाठ्यपुस्तकें खुले बाजार से लगभग गायब हैं, खासकर कक्षा 1 से 8 तक की विभिन्न माध्यम (हिंदी, अंग्रेजी, असमिया, बांग्ला, बोडो) की किताबें।

स्थिति यह है कि जहां कक्षा 9 और 10 की किताबें किसी तरह मिल जाती हैं, वहीं प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर के छात्रों के लिए जरूरी किताबें बाजार में उपलब्ध ही शेष पृष्ठ 5 पर

अंदर पढ़ें

3 ☛ अंतरिक्ष में गूंजा बिहू, असम की संस्कृति ने छुआ आसमान
4 ☛ महिलाओं की भागीदारी
5 ☛ सीमा पर सख्ती, रोजमर्रा पर मार
7 ☛ बुमराह के लिए बीसीसीआई का स्पेशल प्लान

महानगर में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, तीन गिरफ्तार

पति-पत्नी और प्रेमिका मिलकर चला रहे थे हाई-प्रोफाइल नेटवर्क

जन जन विचार
...✍ गुवाहाटी

महानगर में चल रहे एक संगठित सेक्स रैकेट का पुलिस ने भंडाफोड़ कर समाज को झकझोर देने वाला खुलासा किया है। इस मामले में एक युवक, उसकी पत्नी और प्रेमिका को गिरफ्तार किया गया है। जांच में सामने आया है कि यह गिरोह इंटरनेट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए ग्राहकों को फंसाकर अवैध गतिविधियों को अंजाम दे रहा था।

पुलिस के अनुसार, आरोपी लंबे समय से महानगर के विभिन्न इलाकों में नेटवर्क संचालित कर रहे थे। आरोपी युवक इस रैकेट का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, जबकि उसकी पत्नी और प्रेमिका सक्रिय रूप से ग्राहकों से संपर्क साधने और संचालन में मदद करती थीं।

ऑनलाइन माध्यम से फैलाया जाल

जांच में यह तथ्य सामने आया है कि गिरोह सोशल मीडिया, मैसेजिंग ऐप और फर्जी प्रोफाइल का उपयोग कर ग्राहकों को आकर्षित करता था। ग्राहकों को पहले भरोसे में लिया जाता, फिर मोटी रकम वसूली जाती थी। कई मामलों में ब्लैकमेलिंग की भी शिकायतें सामने आई हैं।

पीड़िता के बयान से खुलासा

मामले का खुलासा तब हुआ जब एक पीड़िता ने साहस दिखाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पीड़िता ने आरोप लगाया कि उसे नौकरी और बेहतर जीवन के बहाने जाल में फंसाया गया, बाद में उसके साथ जबर्दस्ती कर उसे इस अवैध धंधे में धकेला गया। विरोध करने पर मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना दी जाती थी।

पुलिस की सख्ती और आगे की जांच

पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और कई अहम डिजिटल साक्ष्य जब्त किए हैं। अधिकारियों का कहना है कि इस रैकेट से जुड़े अन्य लोगों की भी पहचान की जा रही है और जल्द ही और गिरफ्तारियां संभव हैं।

समाज के लिए चेतावनी

यह घटना एक बार फिर यह दर्शाती है कि इंटरनेट और सोशल मीडिया के माध्यम से किस तरह युवाओं को गुमराह कर अपराध के जाल में फंसाया जा रहा है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि किसी भी संदिग्ध ऑनलाइन गतिविधि की तुरंत सूचना दें और सतर्क रहें।

समाज में बढ़ते ऐसे अपराधों के खिलाफ जागरूकता और कड़ी कानूनी कार्रवाई ही समाधान है। युवाओं और अभिभावकों को विशेष सतर्कता बरतने की आवश्यकता है।

सिलचर में नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई

जन जन विचार
...✍ सिलचर

कछार जिले के अंतर्गत सिलचर में पुलिस ने मादक पदार्थों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में हेरोइन बरामद की है। यह सफलता रामनगर बायपास इलाके में चलाए गए विशेष अभियान के दौरान मिली।

पुलिस सूत्रों के अनुसार, गुप्त सूचना के आधार पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में टीम ने अभियान चलाया, जिसमें सिलचर सदर थाना और तारापुर थाना की पुलिस भी शामिल रही।

अभियान के दौरान एक चार पहिया वाहन को रोककर तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान वाहन से 39 साबुन के डिब्बों में छिपाकर रखी गई करीब 450 ग्राम हेरोइन बरामद की गई। इस मामले में पुलिस ने फहीम अहमद बरभुइया और हनीफ अहमद लस्कर नामक दो संदिग्ध तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक (क्राइम) रजत कुमार पाल ने बताया कि जब्त हेरोइन की बाजार कीमत लगभग 2 से 3 करोड़ रुपए आंकी गई है। उन्होंने कहा कि इस तस्करी गिरोह से जुड़े अन्य लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।

पृष्ठ 1 का शेषांश...

अंकवादी मानसिकता

विद्यार्थियों पर मानसिक दबाव लगातार बढ़ रहा है। कम अंक आने पर हीनभावना, अवसाद और आत्मविश्वास की कमी जैसी समस्याएं सामने आ रही हैं। क्या यही वह शिक्षा प्रणाली है, जो हमारे युवाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाएगी?

स्कूलों की प्रतिस्पर्धा भी इस प्रवृत्ति को बढ़ावा दे रही है। '100 प्रतिशत रिजल्ट' और 'टॉपर्स की संख्या' को प्रतिष्ठा का पैमाना बना दिया गया है। कई बार आंतरिक मूल्यांकन में उदारता दिखाकर अंकों को बढ़ाया जाता है, जिससे वास्तविक क्षमता का आकलन ही नहीं हो पाता। यह प्रवृत्ति आगे चलकर उच्च शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में गंभीर असंतुलन पैदा करती है।

शिक्षा का उद्देश्य केवल परीक्षा पास करना नहीं, बल्कि व्यक्तित्व का समग्र विकास होना चाहिए। रचनात्मकता, तार्किक सोच, नैतिक मूल्यों और व्यवहारिक ज्ञान-इन सबकी अनदेखी कर केवल अंकों पर जोर देना शिक्षा के मूल सिद्धांतों के साथ अन्याय है।

अब समय आ गया है कि हम इस 'अंकवादी मानसिकता' पर पुनर्विचार करें। मूल्यांकन प्रणाली को अधिक व्यावहारिक और कौशल आधारित बनाया जाए। विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने और समझने के लिए प्रेरित किया जाए। अभिभावकों और शिक्षकों को भी यह समझना होगा कि अंक ही सफलता का एकमात्र पैमाना नहीं हैं।

अंततः, यदि शिक्षा की गुणवत्ता को बचाना है, तो अंकों की अंधी दौड़ से बाहर निकलना ही होगा। वर्ना हम 'उच्च प्रतिशत' वाले, लेकिन 'कमजोर समझ' वाले युवाओं की एक पूरी पीढ़ी तैयार कर देंगे-जो कागज पर तो सफल होगी, लेकिन जीवन की असली परीक्षा में पिछड़ जाएगी।

नाजिरा : शिमलुगुरी में भारी मात्रा में गोमांस जब्त, दो गिरफ्तार

नाजिरा। शिमलुगुड़ी क्षेत्र में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में गोमांस जब्त किया है। यह कार्रवाई 21 अप्रैल की सुबह विश्वसनीय सूचना के आधार पर की गई। पुलिस के अनुसार, तेतेलीगुड़ी से बिना नंबर प्लेट वाले ई-रिक्शा में गोमांस लेकर कौरी बस्ती की ओर ले जाया जा रहा था। पहले से तैनात पुलिस दल ने वाहन को रोककर तलाशी ली, जिसमें लगभग एक क्विंटल से अधिक गोमांस बरामद हुआ। इस मामले में तेतेलीगुड़ी निवासी आजार अली उर्फ तेतेरा समेत दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

साप्ताहिक राशिफल

24 से 30 अप्रैल 2026।। विक्रम संवत 2083-**मास :** वैशाख, **पक्ष :** शुक्ल, **तिथि :** अष्टमी

मेष **यह** सप्ताह नई शुरुआत के लिए अच्छा है। करियर में मौके मिल सकते हैं। धन लाभ के संकेत हैं, लेकिन खर्च भी बढ़ सकता है। रिश्तों में संयम रखें।

वृषभ **काम** का दबाव रहेगा, लेकिन मेहनत रंग लाएगी। परिवार का सहयोग मिलेगा। स्वास्थ्य पर ध्यान दें, खासकर थकान से बचें।

मिथुन **यह** सप्ताह आपके लिए सकारात्मक रहेगा। नई योजनाएं सफल हो सकती हैं। मित्रों से सहयोग मिलेगा। यात्रा के योग बन रहे हैं।

कर्क **भावनात्मक** उतार-चढ़ाव रह सकता है। करियर में स्थिरता बनाए रखें। निवेश सोच-समझकर करें। परिवार के साथ समय बिताएं।

सिंह **आत्मविश्वास** बढ़ेगा और कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी। पदोन्नति या नई जिम्मेदारी मिल सकती है। प्रेम जीवन अच्छा रहेगा।

कन्या **छोटी**-छोटी बातों में उलझ सकते हैं। धैर्य रखें। आर्थिक मामलों में सावधानी जरूरी है। सेहत सामान्य रहेगी। समय प्रबंधन से कई समस्याएं सुलझ जाएंगी।

तुला **संतुलन** बनाए रखना जरूरी होगा। पार्टनरशिप में लाभ हो सकता है। नई डील या समझौते फायदेमंद रहेंगे। रिश्तों में पारदर्शिता बनाए रखना लाभकारी रहेगा।

वृश्चिक **गुप्त** योजनाएं सफल हो सकती हैं। करियर में बदलाव के संकेत हैं। किसी पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है। अचानक कोई शुभ समाचार मिल सकता है।

धनु **यह** सप्ताह भाग्यशाली रहेगा। पढ़ाई और करियर में अच्छे परिणाम मिलेंगे। धार्मिक या आध्यात्मिक गतिविधियों में रुचि बढ़ेगी।

मकर **काम** में व्यस्तता बढ़ेगी। धैर्य और अनुशासन से सफलता मिलेगी। परिवार में कुछ तनाव हो सकता है, शांत रहें। लंबी अवधि की योजना बनाना फायदेमंद रहेगा।

कुंभ **नई** सोच और रचनात्मकता से लाभ मिलेगा। करियर में प्रगति के योग हैं। दोस्तों के साथ अच्छा समय बीतेगा। तकनीकी या नए आइडिया से फायदा हो सकता है।

मीन **यह** सप्ताह मिश्रित परिणाम देगा। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। सेहत को नजरअंदाज न करें। आत्मविश्वास बनाए रखें, सफलता धीरे-धीरे मिलेगी।

सप्ताह के पर्व/त्योहार

24 अप्रैल (शुक्रवार) : मासिक शिवरात्रि
27 अप्रैल (सोमवार) : मोहिनी एकादशी
29 अप्रैल (बुधवार) : प्रदोष व्रत

भाग्योदय Bhagyoday Astrology
●ज्योतिर्विद् आचार्य अखिलेश्वर शुक्ल
भाग्योदय : पहला तल्ला, सेंट्रल प्लाजा, एमएस रोड
फैंसी बाजार, गुवाहाटी-781001 मो.-94350 40387

अंतरिक्ष में गूंजा बिहू, असम की संस्कृति ने छुआ आसमान

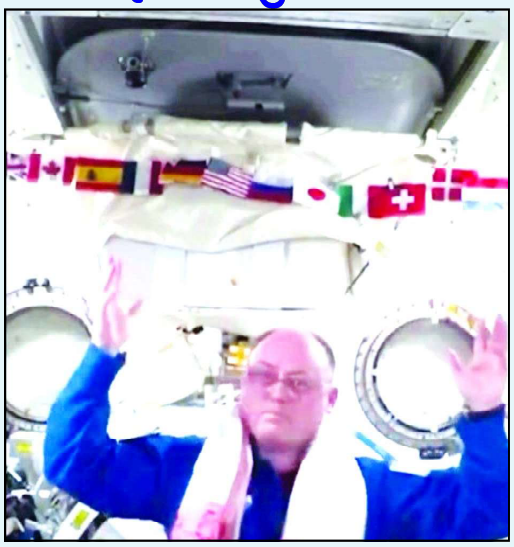

जन जन विचार
...✍ गुवाहाटी

जब धरती पर रंगाली बिहू के रंग बिखरे हुए थे, उसी समय अंतरिक्ष में भी असम की संस्कृति की मधुर धुन सुनाई दी। हाल ही में इंटरनेशनल स्पेश स्टेशन (आईएसएस) पर एक अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री द्वारा बिहू नृत्य करने का वीडियो सामने आया, जिसने न केवल असम बल्कि पूरे देश को गर्व से भर दिया।

इस अनोखे क्षण ने यह साबित कर दिया कि संस्कृति की कोई सीमाएं नहीं होतीं। चाहे धरती हो या अंतरिक्ष, अपनी पहचान और परंपरा हर जगह अपनी छाप छोड़ सकती है। असम के मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत विश्व शर्मा ने भी इस वीडियो की सराहना करते हुए कहा कि यह असमिया संस्कृति के वैश्विक विस्तार का प्रतीक है।

बिहू केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि असम के लोगों की आत्मा है। इसमें खेत-खलिहान की खुशबू, लोकगीतों की मिठास और सामूहिक उत्सव की भावना समाई होती है। जब यही बिहू अंतरिक्ष में पहुंचता है, तो यह केवल एक नृत्य नहीं रहता, बल्कि एक संदेश बन जाता है-हमारी संस्कृति सीमाओं से परे है।

आज के दौर में जब वैश्वीकरण तेजी से बढ़ रहा है, ऐसे दृश्य हमें अपनी जड़ों से जुड़ने की प्रेरणा देते हैं। यह घटना युवाओं के लिए भी एक संदेश है कि आधुनिकता के साथ-साथ अपनी परंपराओं को सहेजकर रखना उतना ही जरूरी है।

हमें भी न्याय चाहिए

श्यामकनु महंत की पत्नी का बड़ा बयान

जन जन विचार
...✍ गुवाहाटी

असम के चर्चित 'जुबिन की मौत' मामले में नया मोड़ तब आया जब अनीता डेका महंत ने अपने पति श्यामकानु महंत का खुलकर बचाव करते हुए कहा कि हमें भी न्याय चाहिए, निर्दोष लोगों को जेल में रखा गया है।

यह मामला असम के प्रसिद्ध गायक जुबिन गर्ग की मौत से जुड़ा है, जिसने पूरे राज्य में भावनात्मक और सामाजिक बहस छेड़ दी है।

अनीता महंता ने अपने पति पर लगे लापरवाही के आरोपों को सिरे से नकारते हुए कहा कि किसी कलाकार को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ले जाना लापरवाही कैसे हो सकती है?

पत्नी का दावा : 7 महीने से निर्दोष जेल में

मीडिया से बातचीत में अनीता ने कहा कि उनके पति पिछले सात महीनों से बिना किसी दोष के जेल में बंद हैं। उन्होंने कहा 'वह सिर्फ असम की संस्कृति को वैश्विक मंच पर ले जाना चाहते थे, क्या यही उनकी गलती है?' उन्होंने यह भी जोड़ा कि जमानत पर सुनवाई चल रही है और उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है।

अनीता महंता ने जुबिन गर्ग को 'पवित्र आत्मा' बताते हुए कहा कि अगर वह आज होते तो इस स्थिति से बेहद आहत होते। उनके अनुसार, जुबीन किसी के दबाव में काम नहीं करते थे, वह वही करते थे जो उन्हें सही लगता था।

सुरों की महफिल में थमी सांसें : आशा भोसले को इवेंट्स इनफिनिटी की भावभीनी श्रद्धांजलि

जन जन विचार
...✍ गुवाहाटी

संगीत जगत की अमर आवाज और 'स्वर कोकिला' आशा भोसले की स्मृति में महानगर के सुर सप्तक संगीतालय प्रांगण में एक भावपूर्ण श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इवेंट्स इनफिनिटी द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में संगीत प्रेमियों ने उपस्थित होकर अपनी प्रिय गायिका को नम आंखों से श्रद्धांजलि दी।

कार्यक्रम का संयोजन अभिनेता अक्की अवकाश, जैन जम्मड़ और निशांत बगड़िया ने किया, जबकि समूचे आयोजन का प्रबंधन संगीतालय के प्रभारी विकास भोवाल के नेतृत्व में किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दो मिनट के मौन के साथ हुई, जिसमें दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई।

इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के असम प्रदेश अध्यक्ष अहमद अली अय्यूबी तथा भाजपा असम प्रोफेशनल्स सेल के प्रदेश संयोजक गौरव सोमानी उपस्थित रहे।

पृष्ठ 1 का शेषांश...

कृत्रिम बाढ़, असली मौतें

के प्राकृतिक रास्ते और खुले चैनल, जो बारिश के पानी को सहजता से बाहर निकाल देते थे। आज वही रास्ते कचरे, सिल्ट और अतिक्रमण से पट चुके हैं। नालों पर इमारतें खड़ी हो गईं, सड़कों ने पानी के रास्ते काट दिए और ड्रेनेज सिस्टम रखरखाव के अभाव में जाम हो गया। नतीजा यह है कि अब बारिश का पानी बहता नहीं, शहर के भीतर ही फंस जाता है और कई बार जानलेवा जाल में बदल जाता है।

इस 'कृत्रिम बाढ़' की सबसे भयावह सच्चाई यह है कि यह केवल जलभराव नहीं लाती, बल्कि चुपचाप मौत लेकर आती है। पिछले दस वर्षों में गुवाहाटी ने कई ऐसी घटनाएं देखी हैं, जो आंकड़ों से कहीं ज्यादा एक सिस्टम की विफलता की कहानी कहती हैं-कहीं खुले तार से करंट लगने से जान गई, कहीं घर में घुसे पानी ने जीवन छीन लिया, कहीं खुले नाले में गिरकर लोग बह गए, तो कहीं मासूम बच्चे इस अव्यवस्था के शिकार बन गए। 2026 में मालीगांव की घटना इस कड़वे सच की ताजा याद है कि शहर में बारिश अब खतरे का दूसरा नाम बन चुकी है।

असम का भूगोल हमेशा से बाढ़ की चुनौती लेकर आया है। ब्रह्मपुत्र और बराक जैसी नदियां हर साल अपना असर दिखाती हैं और असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार 2024 में लाखों लोग इससे प्रभावित हुए। लेकिन गुवाहाटी की स्थिति अलग है-यहां की बाढ़ प्रकृति नहीं, बल्कि हमारी अपनी बनाई हुई समस्याओं का परिणाम है, जो इसे और भी चिंताजनक बना देती है।

यह संकट केवल राजधानी तक सीमित नहीं है। सिलचर, डिब्रूगढ़, नलबाड़ी और बरपेटा जैसे शहर भी हर बारिश में जलजमाव की समस्या से जूझ रहे हैं, जो इस बात का संकेत है कि यह समस्या स्थानीय नहीं, बल्कि पूरे राज्य के शहरी ढांचे में गहराई तक फैली हुई है। सरकार और एजेंसियों के स्तर पर प्रयासों से भी इनकार नहीं किया जा सकता। गुवाहाटी नगर निगम द्वारा नालों की सफाई, डी-सिल्टिंग और जल निकासी सुधार के लिए टेंडर जारी किए गए हैं। 167 करोड़ रुपए की परियोजनाएं स्वीकृत हुई हैं और एक डच कंपनी को ड्रेनेज मास्टर प्लान तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई है, जबकि आईआईटी गुवाहाटी समय-समय पर तकनीकी सुझाव देता रहा है। इसके बावजूद सवाल बना हुआ है कि हर मानसून में हालात क्यों नहीं बदलते।

असल समस्या तकनीक की कमी नहीं, बल्कि क्रियान्वयन और जवाबदेही की कमजोरी है। स्थानीय स्तर की रिपोर्टें बार-बार बताती हैं कि जहां क्रॉस-ड्रेनेज की जरूरत है, वहां काम अधूरा है; जहां पानी के प्राकृतिक रास्ते बहाल होने चाहिए, वहां अवरोध हैं; और जहां आधुनिक ढांचे बनाए गए, वहां जल प्रबंधन की बुनियादी सोच ही शामिल नहीं की गई। ऐसे में फ्लाईओवर और सड़कें विकास के प्रतीक कम और जलजमाव के नए कारण ज्यादा बनते जा रहे हैं।

गुवाहाटी की कहानी अब केवल जलभराव की समस्या नहीं रह गई है, यह भरोसे के संकट में बदल चुकी है। जब एक शहर में बारिश का मतलब खतरा हो जाए और नाले मौत का जाल बन जाएं, तो यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि विकास आखिर किसके लिए और किस कीमत पर हो रहा है। अब जरूरत केवल योजनाएं बनाने की नहीं, बल्कि उन्हें जमीन पर उतारने और हर स्तर पर जवाबदेही तय करने की है।

वरना हर आने वाला मानसून यही कहेगा-पानी वही रहेगा, लेकिन उसकी कीमत हर बार किसी की जान होगी।

संपादकीय

बंगाल : जनता का 'खेल'

पश्चिम बंगाल चुनाव के पहले चरण में करीब 92 फीसदी मतदान ने सियासत की धड़कनें तेज कर दी हैं। यह सिर्फ आंकड़ा नहीं, बल्कि जनता के मूड का साफ संकेत है। सवाल सीधा है-क्या यह 'खेला' का समर्थन है या 'परिवर्तन' की दस्तक ?

सबसे बड़ा बदलाव मतदान के स्वरूप में दिखा। हिंसा के लिए बदनाम बंगाल में अपेक्षाकृत शांतिपूर्ण वोटिंग हुई, जो लोकतंत्र के लिए राहत की खबर है। भाजपा इसे 'भयमुक्त मतदान' की जीत बता रही है, जबकि तृणमूल अपनी योजनाओं का असर मान रही है। हकीकत यह है कि दोनों दावे अधूरे हैं।

ममता बनर्जी की लक्ष्मी भंडार और युवा साथी योजनाओं ने महिलाओं और युवाओं को जोड़ा है, लेकिन बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के मुद्दे अब भी जिंदा हैं। वहीं, मतदाता सूची से कथित फर्जी नाम हटाने की प्रक्रिया ने चुनावी समीकरण बदल दिए हैं। अगर यह सफाई सही है, तो वोट प्रतिशत बढ़ना स्वाभाविक है।

भाजपा के लिए यह चरण निर्णायक है, क्योंकि पिछली जीत का बड़ा आधार यही क्षेत्र था। यहां बढ़त मिली तो सत्ता का रास्ता खुलेगा, वरना 'नर्वस 90' का दबाव भारी पड़ सकता है।

स्पष्ट है-बंगाल की जनता इस बार चुप नहीं है। उसने रिकॉर्ड मतदान कर यह जता दिया है कि फैसला अब वही करेगी। अब देखना है कि यह जनसैलाब 'खेला' को आगे बढ़ाता है या 'परिवर्तन' की कहानी लिखता है।

सुलगता सवाल आपके विचार

एंबुलेंस में तेल खत्म कैसे बचेगी जिंदगी

बिहार के जमुई में हुई यह घटना केवल एक व्यक्ति की मौत नहीं, बल्कि हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था की गंभीर विफलता का प्रतीक है। एक 75 वर्षीय मरीज को बेहतर इलाज के लिए ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में एंबुलेंस का तेल खत्म हो गया और वह भीषण गर्मी में दो घंटे तड़पता रहा। अंतत: उसकी मौत हो गई। सवाल यह है कि क्या अब जीवन और मौत के बीच भी 'तेल' जैसी बुनियादी चीज बाधा बनेगी ?

यह घटना कई स्तरों पर लापरवाही को उजागर करती है। सबसे पहले, एंबुलेंस चालक और संचालन करने वाली निजी कंपनी की जिम्मेदारी बनती है कि वाहन पूरी तरह तैयार हो। 25 किलोमीटर में ही तेल खत्म हो जाना बताता है कि कोई पूर्व योजना या जांच नहीं की गई थी। दूसरी ओर, 'कार्ड से ही तेल मिलेगा' जैसी दलीलें व्यवस्था की संवेदनहीनता को दर्शाती हैं।

स्वास्थ्य सेवाएं किसी भी सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी होती हैं। एंबुलेंस जैसी आपात सेवा में ऐसी चूक अस्वीकार्य है। अगर समय पर वैकल्पिक व्यवस्था की जाती, तो शायद एक जान बच सकती थी।

यह घटना एक बड़ा सवाल खड़ा करती है-क्या हमारी व्यवस्था इतनी कमजोर है कि एक तकनीकी या प्रशासनिक बाधा के कारण मरीज की जान चली जाए ? अब जरूरत है सख्त जवाबदेही तय करने की। दोषियों पर कार्रवाई हो।

महिलाओं की भागीदारी

जन जन विचार
...✍ डॉ. राजें प्रसाद शर्मा

संसद में महिलाओं के 33 फीसदी आरक्षण का बिल गिरने के साथ ही देश में सत्ता में महिलाओं की भागीदारी को लेकर नई बहस छिड़ गई है। जहां एक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संदेश के माध्यम से महिलाओं से माफी मांगी है तो दूसरी और विपक्ष ने इसे अपनी बड़ी जीत और सरकार की हार बताई है। हांलाकि विपक्ष यह भी कह रहा है कि उनका विरोध सीटों के परिसीमन से अधिक है। खैर यह अलग बहस का विषय हो सकता है। पर एक बात साफ हो जानी चाहिए कि सत्ता में महिलाओं की हिस्सेदारी के मामलें में हम दुनिया के देशों से अभी काफी पीछे चल रहे हैं। दुनिया के 190 देशों के आंकड़ों का विष्लेषण करे तो हमारे देश का स्थान 147 वां आता है। दुनिया के देशों में सत्ता में महिलाओं की भागीदारी की बात करें तो वैश्विक स्तर औसत 27.5 फीसदी है। 30 महिला राष्ट्राध्यक्ष महिलाएं है तो दुनिया के केवल 8 देश ही ऐसे हैं जहां महिलाओं की भागीदारी 50 फीसदी से अधिक है। रवांडा, क्यूबा, निकारागुआ, कोस्टारिका, बोलिविया, मैक्सिको, एंडोरा और संयुक्त अरब अमीरात में 50 प्रतिशत से अधिक भागीदारी है। न्यूजीलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड 45 से 50 प्रतिशत महिलाओं का प्रतिनिधित्व है। आज हम महिलाओं की 33 प्रतिशत भागीदारी की बात कर रहे हैं वहीं इस समय दुनिया के 56 देश ऐसे हैं जहां सत्ता में महिलाओं का 33 प्रतिशत प्रतिनिधित्व है।

> खैर इससे यह तस्वीर साफ हो जानी चाहिए कि जब तक संवैधानिक बाध्यता नहीं होगी तब तक महिलाओं की भागीदारी लाख प्रयासों के बावजूद नहीं बढ़ने वाली है। इसके लिए एक सीमा तक सीटों का आरक्षण करना ही होगा। इसका जीता जागता उदाहरण पंचायतीराज व स्थानीय स्वशासन संस्थाएं है। जहां महिलाओं की सीटे आरक्षित होने से आज तस्वीर ही बदल गई है। आज सरपंच पति या प्रधान पति वाली बात भी नहीं रही है। पिछले चुनाव परिणाम भी यह साफ कर चुके हैं कि आज महिलाएं अपने निर्णय स्वयं लेती हैं। यही कारण है कि सरकार बनने और बनाने में महिलाओं मतदाताओं की निर्णायक भूमिका रही है।

एक मोटे अनुमान के अनुसार हालिया चुनावों में 14 राज्यों में महिलाओं की निर्णायक भूमिका रही है। 2024 के लोकसभा चुनावों में भी 19 राज्यों- केंद्र शासित प्रदेशों में महिलाओं ने निर्णायक भूमिका निभाई। इसके साथ ही पिछले कुछ सालों के चुनाव परिणामों का विश्लेषण करें तो यह भी साफ हो जाता है कि लगभग सभी पार्टियों ने महिलाओं को केंद्र में रखकर चुनाव घोषणा पत्र बनाए और महिलाओं को किसी भी नाम से योजना रखते हुए एक निश्चित राशि देने की बात प्रमुखता से की। बिहार, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश या अन्य प्रदेशों में लखपति दीदी या इसी तरह के नाम से मिलती-जुलती योजनाओं में राशि उपलब्ध कराने की रणनीति महिला वोटों को अपनी और करने की रही है, यह दूसरी बात है कि इसका लाभ किस पार्टी को अधिक मिला। एक बात साफ हो जानी चाहिए राजनीतिक पार्टियां कहने को कुछ भी कहें या महिलाओं को आगे लाने की कितनी भी बात करें पर विधानसभा और संसद में महिलाओं की भागीदारी अभी तक बढ़ नहीं पाई है। महिला प्रतिनिधित्व का वैश्विक औसत जहां 27.5 प्रतिशत है वहीं हमारे देश में अभी तक यह 14-15 प्रतिशत तक पहुंच पाया है। रौचक बात यह है कि 2009 की 15 वीं लोकसभा के पहले तक तो हमारे देश में लोकसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व दहाई की संख्या में भी नहीं पहुंचा था। 15 वीं लोकसभा में पहली बार 10.9 प्रतिशत प्रतिनिधित्व हो सका। हांलाकि 1977 में आपातकाल के ठीक बाद की लोकसभा में सबसे कम भागीदारी केवल 3.5 प्रतिशत ही रह गई थी। पर 1977 के हालात अलग थे और उनको अलग करके देखा जाना चाहिए। उस समय आपातकाल के बाद की स्थितियां थी। 18 वीं लोकसभा में 17 वीं लोकसभा की तुलना में 3 महिला सांसद कम हैं। इस तरह से 17वीं लोकसभा में महिलाओं की सर्वाधिक 14.4 प्रतिशत भागीदारी रही।

जहां तक राजनीतिक दलों की बात है तो भले ही महिला आरक्षण बिल का अपनी राजनीतिक प्रतिबद्धता के कारण कांग्रेस व अन्य विपक्षियों के साथ तृणमूल कांग्रेस ने भी विपक्ष में मतदान किया पर लोकसभा और राज्य सभा में टीएमसी दल की महिलाओं की हिस्सेदारी अधिक है। जहां तक कांग्रेस का प्रश्न है तो कांग्रेस की भागीदारी 14.3 प्रतिशत और भाजपा की भागीदारी 12.9 प्रतिशत है। अन्य दलों की भी कमोबेश यही स्थिति है। जहां तक राज्यों का प्रश्न है तो इस समय देश में सर्वाधिक महिला सदस्य छत्तीसगढ़ विधानसभा में है। छत्तीसगढ़ में कुल सदस्यों में 21.1 प्रतिशत महिला सदस्य है। त्रिपुरा में 15 प्रतिशत महिला सदस्य हैं। बाकी देश के अन्य राज्यों में 15 प्रतिशत महिलाएं भी विधानसभा की सदस्य नहीं है। नगालैंड देश का ऐसा प्रदेश है जहां सबसे कम महिला सदस्य हैं। कर्नाटक जैसे राज्य में भी पांच प्रतिशत से कम महिला विधानसभा सदस्य हैं।

खैर इससे यह तस्वीर साफ हो जानी चाहिए कि जब तक संवैधानिक बाध्यता नहीं होगी तब तक महिलाओं की भागीदारी लाख प्रयासों के बावजूद नहीं बढ़ने वाली है। इसके लिए एक सीमा तक सीटों का आरक्षण करना ही होगा। इसका जीता जागता उदाहरण पंचायतीराज व स्थानीय स्वशासन संस्थाएं है। जहां महिलाओं की सीटे आरक्षित होने से आज तस्वीर ही बदल गई है। आज सरपंच पति या प्रधान पति वाली बात भी नहीं रही है। पिछले चुनाव परिणाम भी यह साफ कर चुके हैं कि आज महिलाएं अपने निर्णय स्वयं लेती हैं। यही कारण है कि सरकार बनने और बनाने में महिलाओं मतदाताओं की निर्णायक भूमिका रही है। आने वाले समय में इसमें और अधिक सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा। ऐसे में एक बात साफ हो जानी चाहिए कि बिना आरक्षित सीटों के विधानसभाओं या संसद में महिला सदस्यों की हिस्सेदारी बढ़ने की कल्पना करना बेमानी होगी। यह तो संवैधानिक बाध्यता से ही संभव हो पाएगा। यह सभी राजनीतिक दलों को समझना होगा। यदि महिलाओं की सत्ता में सहभागिता बढ़ानी है तो महिला सीटों का आरक्षण करना ही होगा। यह अवश्य है कि आरक्षण की सीमा आपसी समन्वय व विचार-विमर्श से सर्वसम्मति से तय होता है तो यह बेहतर लोकतांत्रिक परंपरा होगी। राजनीतिक दलों को आपसी आग्रह दुराग्रहों से हटकर इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। गैरसरकारी संगठनों को भी इस दिशा में देश में माहौल बनाना चाहिए। यह साफ है कि अब समय आ गया है जब महिलाओं की हिस्सेदारी तय होनी ही चाहिए।

सीमा पर सख्ती, रोजमर्रा पर मार

नेपाल में 'सौ रुपए' वाले नए नियम से बढ़ता असंतोष

जन जन विचार
...✍ नई दिल्ली

नेपाल में एक प्रशासनिक फैसले ने आम जनजीवन को झकझोर दिया है। बालेन शाह के नेतृत्व में लागू की गई सख्ती के तहत अब 100 नेपाली रुपए से अधिक के सामान पर भारी कस्टम ड्यूटी वसूली जा रही है। यह नियम भले नया न हो, लेकिन इसके कठोर क्रियान्वयन ने सीमावर्ती इलाकों में आर्थिक गतिविधियों को लगभग थाम दिया है।

धारचूला से लेकर सोनौली और जोगबनी तक, वे बाजार जो कभी भारत-नेपाल की साझी संस्कृति और व्यापार के प्रतीक थे, आज सूने पड़ने लगे हैं। नेपाल के नागरिक, जो रोजमर्रा की जरूरतों के लिए भारत

आते थे, अब महंगे करों के कारण या तो खरीदारी सीमित कर रहे हैं या खाली हाथ लौट रहे हैं। इसका सीधा असर भारतीय छोटे व्यापारियों, रिक्शा चालकों और श्रमिकों पर भी पड़ा है।

विपक्षी दलों ने इस कदम को 'अघोषित नाकाबंदी' करार दिया है। उनका तर्क है कि यह निर्णय सीमावर्ती गरीब परिवारों पर असमान रूप से बोझ डालता है। दिलचस्प बात यह है कि हवाई यात्रियों को अपेक्षाकृत अधिक छूट मिलने की बात भी सामने आ रही है, जिससे नीति पर सवाल उठ रहे हैं।

सरकार का पक्ष स्पष्ट है-यह कदम अवैध आयात और राजस्व चोरी पर लगाम लगाने के लिए उठाया गया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या सख्ती का यह तरीका जनहित के अनुकूल है?

आज जरूरत संतुलन की है-राजस्व भी सुरक्षित रहे और आम आदमी की रोटी भी प्रभावित न हो। नेपाल का यह फैसला सिर्फ एक देश का आंतरिक मुद्दा नहीं, बल्कि भारत-नेपाल के सामाजिक और आर्थिक रिश्तों की भी परीक्षा बन गया है।

जलजमाव से राहत की राह पर पटना

जन जन विचार
...✍ पटना

हर साल मानसून में जलजमाव से जूझने वाले पटना के लोगों को इस बार बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड ने शहर में जल निकासी व्यवस्था को मजबूत करने के लिए तेज रफ्तार से काम शुरू कर दिया है, जिसमें कंकड़बाग क्षेत्र प्रमुख फोकस में है।

कंकड़बाग के नंदलाल छपरा इलाके में नए ड्रेनेज पंपिंग स्टेशन (डीपीएस) का निर्माण अब अंतिम चरण में पहुंच चुका है। इसे योगीपुर नाले से जोड़ा जा रहा है, जिससे जल निकासी की क्षमता कई गुना बढ़ेगी।

15 मई तक हर हाल में काम पूरा करने का लक्ष्य

बुडको के प्रबंध निदेशक अनिमेष कुमार पराशर ने निर्माण स्थल का निरीक्षण कर स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सभी कार्य 15 मई तक हर हाल में पूरे किए जाएं। उद्देश्य साफ है-मानसून शुरू होने से पहले नई व्यवस्था को पूरी तरह चालू करना।

कैसे मिलेगी राहत ?

इस परियोजना के तहत-योगीपुर नाले के पानी को नए डीपीएस की ओर डायवर्ट किया जाएगा, जल निकासी की गति तेज होगी, पहाड़ी डीपीएस पर अतिरिक्त दबाव कम पड़ेगा, कंकड़बाग के निचले इलाकों में जलभराव की समस्या घटेगी।

स्थायी समाधान की दिशा में बड़ा कदम

अधिकारियों के अनुसार, यह परियोजना केवल तात्कालिक राहत नहीं बल्कि दीर्घकालिक समाधान की दिशा में अहम पहल है। शहर के अन्य संवेदनशील इलाकों में भी इसी तरह के कार्य जारी हैं, जिससे पूरे पटना की जल निकासी प्रणाली को आधुनिक और प्रभावी बनाया जा सके।

दरभंगा में 2027 तक प्लॉट बिक्री पर रोक

जन जन विचार
...✍ पटना

बिहार के दरभंगा में जमीन कारोबार से जुड़े लोगों के लिए सरकार का ताजा फैसला किसी झटके से कम नहीं है। निर्माणाधीन एम्स के आसपास के इलाकों में जमीन की खरीद-बिक्री पर 31 मार्च 2027 तक रोक लगा दी गई है। यह निर्णय राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप योजना का हिस्सा है, जिसका मकसद क्षेत्र को अव्यवस्थित विकास से बचाकर योजनाबद्ध तरीके से विकसित करना है।

बिहार सरकार ने हाल ही में कैबिनेट बैठक में राज्य के 11 जिलों में नई सैटेलाइट टाउनशिप बसाने का फैसला लिया। इसी के तहत दरभंगा में बहादुरपुर प्रखंड के चांडी, भरौल, बलिया मौजा समेत करीब एक दर्जन गांवों को चिह्नित किया गया है। ये इलाके दरभंगा-मुजफ्फरपुर एनएच- 27 के पास और निर्माणाधीन एम्स के नजदीक स्थित हैं।

पृष्ठ 1 का शेषांश...

मणिपुर : खून, खौफ...

वाल्टे की मौत के बाद हालात और तनावपूर्ण हो गए हैं। उनकी मौत के विरोध में चुराचांदपुर में 22 अप्रैल को 13 घंटे का पूर्ण बंद रखा गया। जोमी, कुकी और ह्मार संगठनों के समर्थन से बुलाए गए इस बंद के दौरान-बाजार, स्कूल, दफ्तर पूरी तरह बंद रहे और सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा।

वाल्टे मई 2023 में हिंसा के दौरान घायल हुए थे और 20 फरवरी 2026 को गुरुग्राम के एक अस्पताल में उनका निधन हो गया।

जोमी समन्वय समिति का कहना है कि विधायक की मौत के 60 दिन बाद भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने चेतावनी दी है कि न्याय मिलने तक आंदोलन जारी रहेगा।

महंगी किताबें : निजी...

कहा गया है कि कई निजी स्कूल, खासकर सीबीएसई से संबद्ध संस्थान, एनसीईआरटी और एससीईआरटी की किताबों के बजाय निजी प्रकाशकों की महंगी किताबें अनिवार्य कर रहे हैं। इससे शिक्षा की लागत बढ़ रही है और समान शिक्षा के उद्देश्य को नुकसान पहुंच रहा है।

एनएचआरसी ने यह भी माना कि यह प्रवृत्ति राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की भावना के खिलाफ है, जो सभी के लिए सस्ती और समान शिक्षा की वकालत करती है। साथ ही, कई किताबें और वर्कबुक थोपना स्कूल बैग पॉलिसी 2020 का भी उल्लंघन है।

आयोग ने राज्यों से पूछा है कि क्या उन्होंने आरटीई की धारा 29 के पालन के लिए कोई दिशा-निर्देश जारी किए हैं। यदि नहीं, तो तुरंत आदेश जारी कर यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि प्राथमिक स्तर पर केवल एनसीईआरटी /एससीईआरटी की किताबें ही लागू हों।

साथ ही, एनएचआरसी ने 30 दिनों के भीतर स्कूल-वार ऑडिट कर यह बताने को कहा है कि कितने स्कूल नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। शिक्षा मंत्रालय से यह भी स्पष्ट करने को कहा गया है कि पाठ्यक्रम और किताबों के निर्धारण में एनसीईआरटी / एससीईआरटी और परीक्षा बोर्ड्स की भूमिका क्या है। आयोग ने सभी संबंधित एजेंसियों को एक्शन टेकन रिपोर्ट निर्धारित समयसीमा में पेश करने का निर्देश दिया है, जिससे इस पूरे मामले में जवाबदेही तय की जा सके।

बाजार में नहीं...

नहीं हैं। नतीजतन, अभिभावक और छात्र निजी प्रकाशकों की महंगी किताबें खरीदने को मजबूर हैं, जिससे शिक्षा का खर्च लगातार बढ़ रहा है।

स्टेट काउंसिल ऑफ एडुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग (एससीईआरटी) द्वारा तैयार की गई किताबें सस्ती, मानकीकृत और सभी के लिए समान शिक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से होती हैं। लेकिन जब ये किताबें ही बाजार में नहीं मिलतीं, तो इसका सीधा असर गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों पर पड़ता है।

अभिभावकों का कहना है कि सरकारी स्कूलों में सीमित वितरण के अलावा, अतिरिक्त जरूरत या निजी स्कूलों के लिए किताबें मिलना मुश्किल है। ऐसे में बुक स्टॉल्स पर निजी प्रकाशकों की गाइड और महंगी किताबें ही विकल्प बचती हैं, जिससे शिक्षा में असमानता और गहराती जा रही है।

शिक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यह संकट केवल आर्थिक नहीं, बल्कि शैक्षिक भी है। शुरुआती कक्षाओं (1-8) में ही जब पाठ्यसामग्री एकसमान नहीं होगी, तो बच्चों का बुनियादी ज्ञान कमजोर होगा और शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित होगी।

जानकारों के अनुसार, समस्या सिर्फ छपाई की कमी नहीं, बल्कि वितरण तंत्र की विफलता और विभिन्न माध्यमों की मांग के अनुरूप आपूर्ति न होने की है।

इस बीच, हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी महंगी किताबों को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए राज्यों और शिक्षा बोर्डों को नोटिस जारी किया है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि निजी स्कूलों द्वारा महंगी किताबें थोपना और सस्ती एनसीईआरटी/एससीईआरटी किताबों की उपलब्धता सुनिश्चित न करना शिक्षा के अधिकार की भावना के खिलाफ है।

ऐसे में असम की स्थिति और भी गंभीर हो जाती है, जहां सरकारी किताबें ही बाजार में उपलब्ध नहीं हैं, जिससे निजी प्रकाशकों की मनमानी को बढ़ावा मिल रहा है।

अब सबसे बड़ा सवाल यही है-जब कक्षा 1 से 8 तक की बुनियादी किताबें ही छात्रों को नहीं मिलेंगी, तो सस्ती और समान शिक्षा का दावा कैसे पूरा होगा?

सरकार के सामने चुनौती साफ है-एससीईआरटी किताबों की खुले बाजार में उपलब्धता सुनिश्चित करना, वितरण व्यवस्था को दुरुस्त करना और निजी प्रकाशकों की बढ़ती पकड़ पर नियंत्रण लगाना।

गणित के जादूगर रामानुजन

26 अप्रैल को पुण्यतिथि

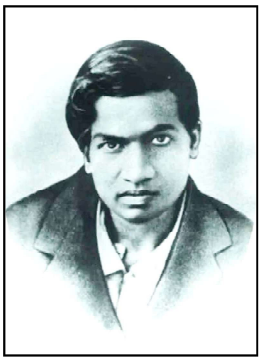

हर साल 26 अप्रैल को हम महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की पुण्यतिथि मनाते हैं। वे ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्ति थे, जिन्होंने बिना ज्यादा पढ़ाई के ही गणित में दुनिया को चौंका दिया।

बचपन से ही खास थे रामानुजन

रामानुजन का जन्म 22 दिसंबर 1887 को तमिलनाडु में हुआ था। बचपन से ही उन्हें गणित से बहुत प्यार था। वे घंटों तक संख्याओं के साथ खेलते रहते थे और खुद ही नए-नए तरीके खोजते थे।

कॉपी में भरे थे अनोखे फॉर्मूले

रामानुजन के पास ज्यादा किताबें नहीं थीं, लेकिन उनकी कॉपियों में हजारों अद्भुत सूत्र (फॉर्मूले) लिखे हुए थे। कई बार तो उन्होंने ऐसे सवाल हल किए, जो बड़े-बड़े गणितज्ञ भी नहीं कर पाते थे।

दुनिया ने माना उनका हुनर

उनकी प्रतिभा को पहचान मिली जब वे इंग्लैंड गए और प्रसिद्ध गणितज्ञ जीएस हार्डी के साथ काम किया। दोनों ने मिलकर गणित में कई महत्वपूर्ण खोजें कीं।

भले ही रामानुजन ने छोटी उम्र में दुनिया छोड़ दी, लेकिन उनके गणितीय सूत्र आज भी पढ़े और इस्तेमाल किए जाते हैं। वे यह संदेश छोड़ गए कि अगर आपमें सीखने की लगन है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं।

रामानुजन सच में 'संख्याओं के जादूगर' थे!

हिंदी अनुवादकों के 84 पदों पर भर्ती, आवेदन शुरू

कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) ने कंबाइंड हिंदी ट्रांसलेटर एग्जामिनेशन 2026 के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। इस भर्ती के माध्यम से केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों एवं विभागों में जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर सहित कुल 84 पदों पर नियुक्ति की जाएगी।

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 23 अप्रैल 2026 से शुरू हो चुकी है और 14 मई 2026 (रात 11 बजे तक) आवेदन किए जा सकते हैं। इच्छुक अभ्यर्थी एसएससी की आधिकारिक वेबसाइट https://ssc.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।

पदों का विवरण

इस परीक्षा के माध्यम से निम्न पदों पर भर्ती होगी-

- जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर
- जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर
- जूनियर ट्रांसलेटर
- सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर
- सीनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर

महत्वपूर्ण तिथियां

आवेदन शुरू : 23 अप्रैल 2026
अंतिम तिथि : 14 मई 2026
फीस जमा करने की अंतिम तिथि : 14 मई 2026
आवेदन सुधार विंडो : 19-20 मई 2026
सीबीटी परीक्षा (पेपर-1) अगस्त-सितंबर 2026

शैक्षणिक योग्यता : उम्मीदवार के पास हिंदी या अंग्रेजी में मास्टर डिग्री (दूसरी भाषा के साथ) होनी चाहिए। साथ ही हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद में डिप्लोमा/सर्टिफिकेट या 2-3 वर्ष का अनुभव आवश्यक है।

आयु सीमा : 18 से 30 वर्ष (01 अगस्त 2026 के अनुसार)। आरक्षित वर्गों को सरकारी नियमों के अनुसार छूट दी जाएगी।

खास बातें :

सभी पद ऑल इंडिया सर्विस लाइबिलिटी के अंतर्गत हैं
चयन के बाद देश में कहीं भी पोस्टिंग हो सकती है
उम्मीदवारों को पोस्ट प्रेफरेंस ऑनलाइन भरनी होगी
गलत जानकारी देने पर उम्मीदवार को डिबार किया जा सकता है

असम एचएस रिजल्ट 28 को होगा घोषित

जन जन विचार
...✍ गुवाहाटी

असम के लाखों विद्यार्थियों का इंतजार अब खत्म होने जा रहा है। असम उच्चतर माध्यमिक शिक्षा परिषद 28 अप्रैल 2026 को कक्षा 12 (एचएस) परीक्षा का परिणाम घोषित करेगा। इस तारीख की पुष्टि डॉ. हिमंत विश्व शर्मा ने अपने आधिकारिक एक्स (पूर्व ट्विटर) माध्यम से की है।

इस वर्ष उच्चतर माध्यमिक परीक्षाएं 11 फरवरी से 16 मार्च 2026 के बीच राज्य के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई थीं। अब मूल्यांकन प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है।

विद्यार्थी अपना परिणाम देखने के लिए असम उच्चतर माध्यमिक शिक्षा परिषद की आधिकारिक वेबसाइट, परिणाम असम पोर्टल (resultsassam.nic.in), डिजीलॉकर पर जा सकते हैं।

डाउनलोड करें अंकपत्र

परिषद की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं, एचएस परिणाम 2026 लिंक पर क्लिक करें, अपना अनुक्रमांक (रोल नंबर) और रोल कोड दर्ज करें, विवरण जमा करते ही परिणाम स्क्रीन पर दिखाई देगा, अंकपत्र डाउनलोड करें और प्रिंट निकाल लें।

सचिन तेंदुलकर : देश के हीरो 'मास्टर ब्लास्टर'

भारत में क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं, बल्कि एक जुनून है। और इस जुनून को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाले महान खिलाड़ी हैं सचिन तेंदुलकर। उन्हें प्यार से 'मास्टर ब्लास्टर' और 'क्रिकेट का भगवान' भी कहा जाता है।

बचपन से ही था क्रिकेट का शौक : सचिन का जन्म 24 अप्रैल 1973 को मुंबई में हुआ था। बचपन में वे बहुत शरारती थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने क्रिकेट खेलना शुरू किया, उनकी जिंदगी बदल गई। उनके कोच रमाकांत आचरेकर ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और उन्हें सही दिशा दी।

रिकॉर्ड्स के बादशाह : सचिन ने बहुत छोटी उम्र (16 साल) में भारत के लिए खेलना शुरू किया। उन्होंने अपने करियर में- 100 अंतर्राष्ट्रीय शतक बनाए, टेस्ट और वनडे में सबसे ज्यादा रन बनाए, 2011 में भारत को वर्ल्ड कप जिताने में अहम भूमिका निभाई।

जन जन की बात जन जन तक
साप्ताहिक
जन जन विचार
RNI Regd No. ASMUL/25/A2367

Head Office : Golapi Market, 1st Floor, Beltola, Guwahati 781029
Branch Office : JanJan Vichar, GMCH Road, Harbala Market, Bhangagarh, Guwahati - 781005
Contact : 69001 26012
Email: official.janjanvichar@gmail.com
Website: WWW.janjanvichar.in

ग्राहक सदस्यता फॉर्म

ग्राहक विवरण

पूरा नाम : ....
पूरा पता : ....
....
मोबाइल : .... ह्वाट्सएप ....
ई-मेल (यदि हो) : ....

सदस्यता विवरण

अवधि : 1 वर्ष शुल्क : रु. 500/- मात्र

सदस्यता के साथ विज्ञापन लाभ

- सालभर (52 अंक) का अखबार नि:शुल्क मिलेगा
- एक नि:शुल्क विज्ञापन (10 सेमी. x 3 कॉलम)
- विज्ञापन प्रकाशन की तिथि ग्राहक की सुविधा अनुसार

भुगतान विवरण

☐ यूपीआई ☐ बैंक ट्रांसफर

Bank Details
JAN JAN VICHAR
Bank : HDFC, Branch : Guwahati
A/C No. 50200116979015
IFSC : HDFC0000264

इस क्यूआर कोड को स्कैन कर जन जन विचार के बैंक खाते में सीधे भुगतान कर सकते हैं।

(कृपया उपरोक्त में किसी एक माध्यम से ही भुगतान करें।)

भुगतान तिथि : .... रसीद संख्या:..............

घोषणा

मैं स्वेच्छा से जन जन विचार साप्ताहिक अखबार की एक वर्ष की सदस्यता ग्रहण करता/करती हूँ एवं सभी शर्तों से सहमत हूँ।

ग्राहक के हस्ताक्षर : तिथि :

कार्यालय उपयोग हेतु

सदस्यता क्रमांक: .... भुगतान प्राप्त रसीद संख्या:.............. प्राप्तकर्ता का नाम : ....
तिथि : .... हस्ताक्षर : ....

बुमराह के लिए बीसीसीआई का स्पेशल प्लान

जन जन विचार
...✍ स्पोर्ट्स डेस्क

बीसीसीआई ने जसप्रीत बुमराह के लिए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (डब्ल्यूटीसी) और 2027 के वनडे वर्ल्ड कप के प्लान बनाना शुरू कर दिया है। एक रिपोर्ट के अनुसार बोर्ड चाहता है कि बुमराह मौजूदा डब्ल्यूटीसी साइकल के सभी टेस्ट मैच खेलें। इस दौरान भारत को कुल 9 टेस्ट मैच खेलने हैं।

बता दें कि, भारत की झोली में डब्ल्यूटीसी की ट्रॉफी को छोड़कर सभी ट्रॉफियां हैं। जिस कारण टीम और बोर्ड को इसकी चाहत बनी रहती है। अब इस ट्रॉफी को भी अपनी झोली में लाने के लिए टीम इंडिया के ब्रह्मास्त्र बुमराह को हर टेस्ट में खिलाने का प्लान बना रहा है। जिसके लिए उन्हें कुछ वनडे सीरीज से आराम दिया जा सकता है।

आईपीएल 2026 के बाद भारतीय टीम 6 जून से चंडीगढ़ में अफगानिस्तान के खिलाफ एक टेस्ट मैच खेलेगी लेकिन वह डब्ल्यूटीसी के साइकल में नहीं है। उसके बाद भारत को इस साल श्रीलंका और न्यूजीलैंड के साथ भी 2-2 टेस्ट मैच खेलने हैं। अगले साल जनवरी में ऑस्ट्रेलिया की टीम भारत दौरे पर आएगी और दोनों टीमों के बीच 5 टेस्ट मैच की बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी खेली जाएगी।

रिपोर्ट में बताया गया है कि इस साल भले ही 2027 के वनडे वर्ल्ड कप को लेकर शोर रहेगा, लेकिन भारत की प्राथमिकता मौजूदा डब्ल्यूटीसी साइकल में टीम की उम्मीदों को जिंदा करने पर रहेगा।

सैफ महिला चैंपियनशिप से पाक हटा

जन जन विचार
...✍ स्पोर्ट्स डेस्क

दक्षिण एशिया के सबसे प्रमुख महिला फुटबॉल टूर्नामेंट सैफ वुमेंस चैंपियनशिप 2026 को बड़ा झटका लगा है। पाकिस्तान ने भारत में आयोजित होने वाली इस प्रतियोगिता से अपना नाम वापस ले लिया है। पाकिस्तान फुटबाल फेडरेशन (पीएफएफ) ने आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि भारत-पाकिस्तान के बीच बढ़ते राजनीतिक तनाव के कारण यह निर्णय लिया गया है।

गोवा में होगा आयोजन, छह टीमें बचीं

यह टूर्नामेंट 25 मई से 6 जून तक पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, गोवा में खेला जाएगा। पाकिस्तान के हटने के बाद अब प्रतियोगिता में केवल 6 टीमें भाग लेंगी। अब टूर्नामेंट में शामिल टीमें हैं- भारत (मेजबान), बांग्लादेश (डिफेंडिंग चैंपियन), नेपाल, श्रीलंका, भूटान और मालदीव। इन टीमों को दो समूहों में बांटा गया है।

भारत और बांग्लादेश पर रहेगी नजर

भारत इस टूर्नामेंट का सबसे सफल देश रहा है, जिसने 2010, 2012, 2014, 2016 और 2019 में खिताब जीते। वहीं बांग्लादेश ने 2022 और 2024 में लगातार दो बार चैंपियन बनकर अपनी मजबूत दावेदारी साबित की है।

खेल की राजनीति : पाकिस्तान का यह फैसला केवल एक खेली निर्णय नहीं बल्कि क्षेत्रीय राजनीति के असर को भी दर्शाता है। इससे पहले भी पाकिस्तान जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप (तमिलनाडु), एशिया कप (राजगीर) जैसे आयोजनों से दूरी बना चुका है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला पाकिस्तान महिला फुटबॉल के विकास के लिए नुकसानदायक हो सकता है। लंबे समय बाद टीम को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर खुद को साबित करने का मौका मिल रहा था, जो अब छिन गया।

ओलंपिक में क्रिकेट की मेजबानी करेगा नाइट राइडर्स का घरेलू मैदान

जन जन विचार
...✍ स्पोर्ट्स डेस्क

आईसीसी के सीईओ संजोग गुप्ता ने कहा कि 2028 में होने वाले ओलंपिक खेलों में क्रिकेट प्रतियोगिता लॉस एंजिलिस नाइट राइडर्स के घरेलू मैदान पर आयोजित की जाएगी, जिसका 23 अप्रैल को शिलान्यास किया गया। उन्होंने कहा कि यह इतिहास का एक महत्वपूर्ण क्षण है, क्योंकि आज हम जिस चीज की नींव रख रहे हैं, वह सिर्फ एक क्रिकेट मैदान नहीं है। हम एक वादे की नींव रख रहे हैं। एक ऐसा वादा जिसे पूरा करने में 128 साल लगे। गुप्ता लॉस एंजिलिस 2028 ओलंपिक खेलों में क्रिकेट के आयोजन स्थल के शिलान्यास समारोह में बोल रहे थे। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति (आईओसी) ने क्रिकेट को लॉस एंजिलिस खेलों में शामिल करने की मंजूरी दी है और गुप्ता ने कहा कि इससे इस खेल के बढ़ते प्रभाव का पता चलता है। उन्होंने कहा, 'दुनिया का दूसरा सबसे लोकप्रिय खेल इतने लंबे समय से ओलंपिक मंच से गायब रहा। जब अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने लॉस एंजिलिस 2028 खेलों में क्रिकेट को शामिल करने की औपचारिक मंजूरी दी, तो यह केवल घोषणा मात्र नहीं थी। इससे इस बात का पता चलता है कि ओलंपिक में उन खेलों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए जिन्हें अरबों लोग पसंद करते हैं।'

पृष्ठ 1 का शेषांश...

तीन शव बरामद

जुड़ा माना जा रहा है। पुलिस के अनुसार, तीनों लोग 19 अप्रैल से लापता थे। पश्चिमी गुवाहाटी के डीसीपी बालन देउरी ने बताया कि शव वशिष्ठ नदी, मरा भरलू नदी और लचितगढ़ के पास एक तालाब से बरामद किए गए।

पहचान किए गए मृतकों में-अख्तर अली (28)- हातीगांव के नोटबोमा निवासी, मिर्गी के मरीज, जिनका शव वशिष्ठ नदी से मिला।

असीम कलिता- दातालपाड़ा निवासी, जिनका शव ज्योतिकुची इलाके में मरा भरलू नदी से बरामद हुआ।

वहीं, लचितगढ़ के पास तालाब से मिले तीसरे शव की पहचान अब तक नहीं हो सकी है।

इससे पहले, धारापुर की 32 वर्षीय पायल नाथ की मौत मालीगांव चारिआली में उफनते नाले में बहने से हो चुकी है, जिसने शहर में जलजमाव के खतरे को और उजागर कर दिया है।

स्वप्ननील पॉल (कामरूप मेट्रो डीसी) ने बताया कि पामोही क्षेत्र के एक निजी परिसर में तालाब से शव मिलने की सूचना मिली है, जबकि अन्य मामलों में विस्तृत जानकारी जुटाई जा रही है। प्रशासन का कहना है कि मौत के वास्तविक कारणों की पुष्टि के लिए जांच जारी है, लेकिन लगातार सामने आ रही घटनाएं यह संकेत दे रही हैं कि शहर में जलजमाव अब सिर्फ असुविधा नहीं, बल्कि जीवन के लिए गंभीर खतरा बन चुका है।

नाले जाम, सिस्टम फेल

ड्रेनेज सिस्टम पर दबाव बढ़ा है, जिससे शहर के कई हिस्सों में व्यापक जलभराव हुआ और जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ। मुख्य सचिव ने साफ कहा कि नालों में फेंका गया प्लास्टिक कचरा जल निकासी को बाधित कर रहा है, इसलिए मानसून से पहले इसकी सफाई बेहद जरूरी है। उन्होंने नागरिकों और प्रशासन दोनों से जिम्मेदारी निभाने की अपील की। उन्होंने वशिष्ठ, बेलतला और जोराबाट-बर्नीहाट से आने वाले भारी जल प्रवाह वाले इलाकों के लिए दीर्घकालिक और अलग योजना बनाने की जरूरत भी बताई।

मालीगांव में हालिया फ्लैश फ्लड में महिला की मौत पर शोक व्यक्त करते हुए सरकार ने जांच और जवाबदेही तय करने का भरोसा दिया है।

गौरतलब है कि 19 अप्रैल को कुछ ही घंटों में 100 मिमी से अधिक बारिश ने रुक्मिणीगांव, हातीगांव, अनिल नगर, राजगढ़ समेत कई इलाकों को जलमग्न कर दिया था, जिससे शहर की ड्रेनेज व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं।

शत्रु की जीभ क्यों खींचती हैं मां पीतांबरा

मां बगलामुखी का स्वरूप जितना उग्र दिखता है, उतना ही गहरा उसका आध्यात्मिक अर्थ है। शत्रु की जीभ खींचने का दृश्य कोई क्रूरता नहीं, बल्कि नियंत्रण और संतुलन का प्रतीक है।

पौराणिक कथा के अनुसार, मदन असुर को वाक-सिद्धि प्राप्त थी-वह जो बोलता, वही सच हो जाता। जब उसकी वाणी अत्याचार का माध्यम बनी, तब देवी ने

उसकी जीभ पकड़कर उसकी शक्ति को स्तंभित कर दिया। यहीं से 'स्तंभन शक्ति' का सिद्धांत सामने आता है-अर्थात् गलत शक्ति को रोक देना।

यह प्रतीक आज भी उतना ही प्रासंगिक है। असल में, जीभ सिर्फ शत्रु की नहीं, हमारी अपनी वाणी का भी प्रतीक है। अनियंत्रित शब्द, झूठ, कटुता और अहंकार-ये सब हमारे सबसे बड़े शत्रु हैं। मां पीतांबरा का संदेश स्पष्ट है-जो अपनी वाणी पर नियंत्रण नहीं रखता, वह स्वयं अपने विनाश का कारण बनता है।

राजनीति, समाज और व्यक्तिगत जीवन-हर जगह शब्दों की ताकत निर्णायक होती है। झूठे प्रचार, षड्यंत्र और नफरत भरे भाषण आज के 'मदन असुर' हैं। ऐसे में यह देवी स्वरूप हमें सिखाता है कि असत्य और अन्याय की आवाज को रोकना भी धर्म है।

इसलिए मां बगलामुखी की आराधना केवल बाहरी शत्रुओं के नाश के लिए नहीं, बल्कि भीतर के क्रोध, लोभ और अहंकार को शांत करने के लिए भी है। असली विजय तब है, जब हम अपनी वाणी और विचारों को साध लें-यही इस उग्र प्रतीक का शांत संदेश है।

हरिद्रा सरोवर से प्रकट हुईं देवी

शत्रुनाशक देवी बगलामुखी को देवी माता पार्वती का ही उग्र रूप बताया जाता है। इनके बारे में पौराणिक कथा के अनुसार जानकारी मिलती है कि सत युग में सृष्टि पर आए भारी तूफान के कारण सभी प्राणियों को प्रलय का सामना करना पड़ा था। तब त्राहि-त्राहि मच गई थी, उस समय भगवान विष्णु पृथ्वी की आपदा के निवारण के लिए आगे आए थे और देवी पार्वती को प्रसन्न करने के लिए सौराष्ट्र क्षेत्र के हरिद्रा सरोवर के निकट उन्होंने घोर तपस्या भी की थी।

भगवान विष्णु द्वारा की गई तपस्या से प्रसन्न होकर देवी, बगलामुखी के रूप में हरिद्रा सरोवर से प्रकट हुई थीं और उसी ने समस्त ब्रह्मांड के विनाश को रोक कर प्राणियों की रक्षा की थी।

रावण भी करता था देवी बगलामुखी की पूजा

कहते हैं लंकापति रावण भी शत्रुओं के विनाश के लिए देवी बगलामुखी की ही पूजा किया करता था। इसी तरह से पांडव भी अपने अज्ञातवास के समय अपनी रक्षा हेतु आराध्य देवी बगलामुखी की ही पूजा किया करते थे।

बताया जाता है कि बगला शब्द की उत्पति 'वल्या' से बताई जाती है, जिसका अर्थ लगाम है। कुछ भी हो देवी बगलामुखी के वैसे भी 108 नाम जाने जाते हैं, जो देवी की शक्तियों का परिचय देते हैं।

भारतीय सिनेमा के जनक दादा साहेब फाल्के

जब भारत में सिनेमा का नामोनिशान भी नहीं था, तब एक व्यक्ति ने सपनों को परदे पर उतारने का साहस किया—दादा साहेब फाल्के। 30 अप्रैल 1870 को महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर में जन्मे धुंडीराज गोविंद फाल्के ने भारतीय सिनेमा की ऐसी नींव रखी, जिस पर आज विशाल फिल्म उद्योग खड़ा है।

30 अप्रैल को जिनकी जयंती है

फाल्के ने 1913 में राजा हरिश्चंद्र का निर्माण कर इतिहास रच दिया। यह भारत की पहली पूर्ण लंबाई की फीचर फिल्म थी, जिसने देश में चलचित्रों के नए युग की शुरुआत की। सीमित संसाधनों, तकनीकी चुनौतियों और सामाजिक रूढ़ियों के बावजूद उन्होंने यह साबित किया कि भारतीय कहानियां भी परदे पर जीवंत हो सकती हैं।

उनकी फिल्मों में पौराणिक कथाओं का गहरा प्रभाव दिखता है-लंका दहन, श्री कृष्ण जन्म जैसी कृतियां न केवल मनोरंजन थीं, बल्कि सांस्कृतिक पहचान का भी माध्यम बनीं। उस दौर में जब महिलाओं का फिल्मों में अभिनय वर्जित था, फाल्के ने दुर्गाबाई कामत और कमलाबाई गोखले को अवसर देकर सामाजिक सोच को नई दिशा दी।

फाल्के केवल निर्देशक ही नहीं, बल्कि तकनीकी नवाचार के अग्रदूत भी थे। कैमरा, सेट डिजाइन, संपादन-हर क्षेत्र में उन्होंने प्रयोग किए। उनकी पत्नी सरस्वतीबाई फाल्के का योगदान भी उल्लेखनीय रहा, जो भारत की पहली महिला फिल्म संपादक बनीं।

उनकी स्मृति में 1969 से दिया जाने वाला दादा साहेब फाल्के पुरस्कार आज भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान है। 16 फरवरी 1944 को उनके निधन के बाद भी उनकी विरासत जीवित है।

आज जब भारतीय सिनेमा वैश्विक मंच पर अपनी पहचान बना चुका है, तब हर फ्रेम में फाल्के के उस साहस और दृष्टि की झलक दिखाई देती है, जिसने कभी एक असंभव सपने को हकीकत में बदला था।

प्रकृति का चमत्कार : गुलाबी है लेक हिलियर का पानी

दुनिया में कई प्राकृतिक अजूबे हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की लेक हिलियर उन में से एक ऐसा रहस्य है, जो पहली नजर में ही चौंका देता है। गहरे नीले समुद्र और हरे-भरे जंगलों के बीच बसी यह झील अपने चटक गुलाबी रंग के कारण वर्षों से वैज्ञानिकों और पर्यटकों दोनों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है।

इस अनोखे रंग के पीछे कोई जादू नहीं, बल्कि शुद्ध विज्ञान काम करता है। झील के पानी में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव-खासकर ड्युनेलिएला सलीना-इस रंग के मुख्य कारण हैं। यह शैवाल अत्यधिक खारे पानी में जीवित रहता है और सूर्य की तेज रोशनी से खुद को बचाने के लिए कैरोटीनॉयड नामक पिगमेंट बनाता है, जो लाल-गुलाबी रंग देता है।

लेक हिलियर की सुंदरता को निहारने का सबसे अच्छा तरीका सीनिक फ्लाइट है। एम्प्रेरेंस शहर से उड़ान भरकर पर्यटक ऊपर से इस झील के नजारे का आनंद लेते हैं।

इसके अलावा, यहां पाए जाने वाले हेलोफाइल बैक्टीरिया और अन्य सूक्ष्म जीव भी इस रंग को गहरा करने में योगदान देते हैं। आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकों ने यह स्पष्ट किया है कि यह झील एक जटिल माइक्रोबायोम का उदाहरण है, जहां कई सूक्ष्म जीव मिलकर

इस अनोखे रंग को स्थायी बनाए रखते हैं। खास बात यह है कि झील का पानी किसी बर्तन में निकालने पर भी गुलाबी ही दिखाई देता है।

जहां तक सुरक्षा का सवाल है, यह पानी जहरीला नहीं है, लेकिन अत्यधिक खारेपन के कारण इसमें तैरना आसान नहीं। साथ ही, इस नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र को बचाने के लिए यहां मानव हस्तक्षेप सीमित रखा गया है।

लेक हिलियर हमें यह सिखाती है कि प्रकृति के रहस्य जितने सुंदर होते हैं, उतने ही वैज्ञानिक भी। जरूरत है इन्हें समझने और सहेजने की, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इस गुलाबी चमत्कार को देख सकें।

पूर्वांचल प्रिंट्स की ओर से राजनाथ पाल द्वारा जीएमसीएच रोड, हरबाला मार्केट, भांगागढ़, गुवाहाटी-781005 से प्रकाशित एवं मुद्रित। संपर्क : 69001 26012
ई-मेल:official.janjanvichar@gmail.com, वेबसाइट: www.janjanvichar.in
● कार्यकारी संपादक : सुभाष कुमार चौधरी ●संपादक : धनेश्वर चौधरी